भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – *187

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक शांति में भारत का योगदान

***187. श्री अरुण कुमार सागर**:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी ने वैश्विक शांति की दिशा में किस प्रकार योगदान दिया है;

(ख) आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों और इंटरपोल के साथ सहयोग के माध्यम से सुरक्षा में कितना सुधार किया गया है;

(ग) साइबर सुरक्षा और डिजिटल कूटनीति के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है; और

(घ) सरकार की बहुपक्षीय कूटनीति के परिणामस्वरूप भारत की वैश्विक भूमिका किस हद तक सुदृढ़ हुई है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"वैश्विक शांति में भारत का योगदान" के संबंध में दिनांक 31.07.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 187 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। यह समर्थन विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में इसका विशिष्ट योगदान शामिल है। यह योगदान 8 बार भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता में भी परिलक्षित होता है और 2028–29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। प्रत्येक कार्यकाल में भारतीय हितों के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय एजेंडा पर रखा जाता रहा है, जिनमें पिछला वर्ष 2021–22 में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी मुद्दे से संबंधित था। वर्ष 2028–29 की उम्मीदवारी के लिए छह प्राथमिकताएँ हैं: (i) वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ (ii) पुनर्गठित बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाना (iii) भविष्य के अनुकूल शांति स्थापना (iv) एआई के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरों पर विचार करना (v) समुद्री संसाधनों की सुरक्षा करना (vi) आतंकवाद संबंधी वित्त पोषण का मुकाबला करना।

भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जिसमें लगभग 3,00,000 शांति सैनिक संयुक्त राष्ट्र के 50 से अधिक मिशनों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में, 11 सक्रिय मिशनों में से 9 में 4,200 भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं, जो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। शांति स्थापना गतिविधियों में भारत की भागीदारी को संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों द्वारा उच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिसे हमारे शांति सैनिकों द्वारा प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों और सम्मान–पत्रों में दर्शाया गया है।

हाल के दिनों में, वैश्विक शांति से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के साथ–साथ अन्य मंचों पर भी चर्चा हुई है। भारत ने दृढ़ता से अपने विचार को आगे बढ़ाया है कि स्थायी और दीर्घकालिक शांति प्राप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति सबसे अच्छे साधन हैं। यह यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया घटनाक्रम के साथ–साथ खाड़ी संघर्ष के संबंध में बताया गया है।

आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में, भारत ने शून्य–सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति की जोरदार वकालत की है और राष्ट्रों के इस अधिकार को मान्यता दी है कि वे आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करें। वर्ष 1996 से, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन को अंगीकृत करने का भी आह्वान किया है। भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों द्वारा स्थापित आतंकवाद–रोधी तंत्र का समर्थन करता है, जिनमें संकल्प 1267 और 1988 और उनके उत्तरवर्ती संकल्प शामिल हैं, जो अल–कायदा, इराक और लैवेंट के इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल) और संबंधित संगठनों जैसे लश्कर–ए–तैयबा (एलईटी) और जैश–ए–मोहम्मद (जेईएम) पर प्रतिबंधों से संबंधित हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में, आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों की जांच के संबंध में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है।

साइबर सुरक्षा के संबंध में, भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित सभी प्रक्रियाओं में भाग लेता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आईसीटी के क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर नव स्थापित स्थायी वैश्विक तंत्र और आईसीटी के उपयोग में जिम्मेदार राज्य व्यवहार को आगे बढ़ाना शामिल है। भारत ने फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की, जहाँ उसने एआई के

मानव–केंद्रित दृष्टिकोण – 'मानव' – को प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ नैतिक और एथिकल सिस्टम; जवाबदेह शासन; राष्ट्रीय संप्रभुता; सुलभ और समावेशी; वैध और कानूनी सिस्टम है।

भारत की वैश्विक भूमिका को इसकी प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बहुपक्षीय कूटनीति से लाभ हुआ है। इसके हालिया उदाहरणों में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज़ (आईटीएलओएस) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के उपाध्यक्ष के लिए भारतीय उम्मीदवारों का चुनाव शामिल है। भारत की उम्मीदवारी को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन मिला है, उदाहरण के लिए, सातवें कार्यकाल (2026–2028) के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का चुनाव, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए पुन: चुनाव (2025–2029), संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (2026–2028),किम्बरले प्रक्रिया के 2025 के उपाध्यक्ष और 2026 के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की परिषद के लिए पुनः चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की परिषद, डाक संचालन परिषद (पीओसी) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की प्रशासन परिषद 2026–2029 के लिए चुनाव।

हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सुधार के लिए भी एक सशक्त आवाज रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अंतर–सरकारी वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

******